

F.No.11013//2007-Estt.(A)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
(Department of Personnel & Training)

North Block,  
New Delhi,  
Dated the 13<sup>th</sup> November, 2007.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : CCS(Conduct) Rules, 1964 – Provisions of rule 15 regarding the holding of  
elective office by Government servants in Co-operative Societies etc.

\*\*\*\*\*

As a number of references are being received in this Department regarding the need for obtaining permission by Government servants to hold elective offices in Co-operative Societies and other bodies, the necessity to reiterate the relevant provisions of the CCS(Conduct) Rules, 1964 has been felt. Rule 15(1) (c) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 provides that no Government servant shall, except with the previous sanction of the Government hold an elective office, or canvass for a candidate or candidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not. Under Rule 15 (2)(d), a Government servant may, without the previous sanction of the Government, take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) of a literary, scientific or charitable society or of a club or similar organization, the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any other law for the time being in force. Rule 15 (2)(e) provides that no previous permission is required for taking part in the registration, promotion or management (not involving the holding of elective office) of a co-operative society substantially for the benefit of Government servants, registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or any other law for the time being in force.

2. It needs to be stressed that the entire time of the Government servant should be available to the Government and that no activities unconnected with his or her official duties should be allowed to interfere with the efficient discharge of such duties. All Ministries are requested to ensure that the participation of Government servants in the activities of cooperative societies conform to the above provisions and does not interfere with the discharge of their official duties.

3. The relevant Acts and bye-laws of the Co-operative Societies contain necessary provisions regarding eligibility of candidates to contest election including restrictions on tenure/number of terms.

4. The request from Government servants for permission to participate in the activities of Co-operative Societies and other bodies may also be examined keeping in view the provisions of the relevant Act and bye-laws governing the activities of such societies apart from the aforesaid provisions of rule 15(1) & (2) of the CCS(Conduct) Rules, 1964.



(P. Prabhakaran)  
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to :

1. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
2. Union Public Service Commission, New Delhi.
3. Central Vigilance Commission, New Delhi.
4. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
5. All Union Territory Administrations.
6. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
7. All attached and subordinate offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
8. All Officers and sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.

सं. 11013/11/2007-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 13<sup><sup>th</sup></sup> नवम्बर, 2007

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय: केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 - सहकारी समितियों आदि में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद को धारण करने से संबंधित नियम 15 के प्रावधान ।**

चूँकि इस विभाग में सहकारी समितियों और अन्य निकायों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित पद को धारित करने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं अतः केन्द्रीय सचिवालय सेवा आचरण (नियमावली), 1964 के संगत प्रावधानों को दोहराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है । केन्द्रीय सचिवालय सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15 (1)(ग) में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पहले ली गई सरकारी स्वीकृति को छोड़कर किसी भी निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा निगमित नहीं हों, में किसी निर्वाचित पद को धारित नहीं करेगा अथवा किसी निर्वाचित पद हेतु एक उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेगा । तथापि, नियम 15 (2)(घ) के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बगैर ही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा चैरिटेबल सोसाइटी अथवा क्लब अथवा सदृश संगठन, जिसके उद्देश्य अथवा लक्ष्य खेल-कूद सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की गतिविधियों के संवर्धन से जुड़े हुए हों, के पंजीकरण संवर्धन अथवा प्रबंध (इसमें निर्वाचित पद को धारित करना शामिल नहीं है) में भाग ले सकता है । नियम 15 (2) (ड) में यह व्यवस्था की गई है कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत किसी सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण, संवर्धन अथवा प्रबंधन (इसमें निर्वाचित पद शामिल नहीं है) में यथार्थतः सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ भाग लेने हेतु किसी भी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है ।

2. इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारी का पूरा समय सरकार के लिए उपलब्ध होना चाहिए तथा उसके सरकारी कर्तव्यों से संबंध नहीं रखने वाली गतिविधि को इन कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करने में रूकावट पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । सभी मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि सहकारी सोसाइटियों की